



देश की उपासना



देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 04

अंक - 91

जौनपुर शुक्रवार, 14 नवम्बर 2025

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

जांच के घेरे में

चांसलर जवाब

अहमद सिद्दीकी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के निदेशक और संस्थापक ट्रस्टी, जवाब अहमद सिद्दीकी, इस हफ्ते की शुरुआत में लाल किले के पास हुए घातक दिल्ली विस्फोट के बाद गहन जांच के केंद्र में आ गए हैं। उनकी ओर सबसे पहले तब ध्यान गया जब फरीदाबाद में कथित प्लेफ़ोश आतंकी मोड्यूल से जुड़े तीन डॉक्टर, डॉ. उमर नबी, डॉ. मुजम्मिल शकील (जिन्हें मुजम्मिल अहमद गनई के नाम से भी जाना जाता है) और शाहीन शाहिद, अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में कार्यरत पाए गए। इस खोज ने जांचकर्ताओं को इस संस्थान और इसे चलाने वाले लोगों की ओर बारीकी से जांच करने के लिए प्रेरित किया। सुरक्षा एजेंसियों की निगह में आई फरीदाबाद की अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के सभी दस्तावेजों का फ़ॉरेंसिक ऑडिट होगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इसका आदेश दिया है। साथ ही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेनदेन की जांच करेगी। दूसरी वित्तीय एजेंसियां भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े पैसों के लेनदेन की जांच करेगी। जांच एजेंसियां संस्थानों के रेकॉर्ड खंगालने के साथ ही यूनिवर्सिटी की नियुक्ति प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। कुछ वर्षों में यहां तैनात हुए डॉक्टरों और प्रफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया स्टूडेंट्स और सर्विस दे रहे कश्मीरी डॉक्टरों के वेरिफिकेशन और डॉ. शाहीन और डॉ. मुजम्मिल शकील ने एक साल के दौरान कितनी छुट्टियां लीं, उस दौरान कहा गए इन सभी पर नंच होगी।

गन्ने के दाम को

लेकर हिसक

प्रदर्शन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कनाटक के बागलकोट में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। गोदावरी शुगरस फ़ैक्ट्री के अंदर गन्ने से लदे 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में अफ़रा-तफ़री मच गई। दृश्यों और शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, फ़ैक्ट्री के अंदर कतार में खड़े ट्रैक्टर आग की लपटों में फिरे हुए दिखाई दे रहे थे और आसपास घना धुआं छा गया था। अफ़रा-तफ़री के बीच दो मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी गई। मौके पर पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी, जिससे जिला प्रशासन को स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल मौके पर मौजूद थे और अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि, किसान नेता सुभाष शिराबुर ने इस बात से इनकार किया कि आगजनी के लिए किसान जिम्मेदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि फ़ैक्ट्री से जुड़े लोगों ने पुलिस अधिकारियों के सामने हिंसा की। गन्ने से भरे ट्रैक्टरों में आग लगाने वाले हम नहीं हैं। एसपी साहब खुद वहाँ मौजूद थे। उधर से पत्थर फेंके गए, और हमारे लोग और कुछ पुलिसवाले भी घायल हुए

बिहार में फिर बहार, नीतीश सरकार

बिहार, (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुका है। तमाम एग्जिट पोल ने साफ़ इशारा किया था कि एनडीए को महिलाओं, ओबीसी और ईबीसी वर्ग का बंपर समर्थन मिला है। रुझान भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में दोनों चरणों में कुल मतदान 66.91 फीसदी रहा था। मतदान के दोनों ही चरणों में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6 फीसदी रहा था। वहीं पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8 फीसदी ही रहा। इन आंकड़ों से साफ़ हो जाता है कि पुरुषों के



मुकाबले महिलाओं ने करीब 10 फीसदी ज्यादा मतदान किया। रुझानों में एनडीए को 190, महागठबंधन को 49 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाने के संकेत मिल रहे हैं। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो एनडीए बिहार में इतिहास रच देगा। जीविका दीदी योजना ने

बदल डाला सियासी माहौल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में जीविका दीदी योजना के तहत 1.30 करोड़ महिलाओं को दस-दस हजार रुपये दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को नीतीश सरकार की इस योजना की शुरुआत

महिलाओं को दस-दस हजार रुपये देकर की थी। तीन अक्टूबर को 25 लाख नई महिलाओं को दस-दस हजार रुपये दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया। इसकी वजह से महिलाओं में नीतीश कुमार को काफी लोकप्रियता मिली। 2006 की ये योजना भी बनी भविष्य की गेमचेंजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लड़कियों को साइकिल और स्कूल की पोशाक दी जाती है। इस योजना ने बिहार की उन बेटियों को काफी मजबूत किया, जो स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थीं।

पूर्व पीएम नेहरू की 125वीं जयंती, पीएम मोदी और खरगे ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आजादी के नायक और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 14 नवंबर को नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर देशभर में बच्चों और शिक्षकों के बीच उत्सव और यादों का माहौल रहता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश साझा करते हुए कहा, 'आज हम स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मना रहे हैं। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। हम स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका को याद करते हैं। नेहरू, जिन्हें बच्चों का प्रिय चाचा नेहरू कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने देश को आजादी के बाद नए रास्ते दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की उनकी सोच आज भी भारत की पहचान का हिस्सा मानी जाती है। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने संसद प्रणाली को मजबूत किया, वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा, अनुसंधान और विकास को देश की प्राथमिकताओं में शामिल किया। उनकी 125वीं जयंती पर देशभर में एक बार फिर उनके विचारों और आदर्शों पर चर्चा तेज हुई है।



अब चौनमैन भी बन सकेंगे लेखपाल, यूपी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए चौनमैन के लिए लेखपाल पद पर पदोन्नति का मार्ग खोल दिया है। वित्त मंत्री सुरेशा खन्ना ने बताया कि पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में से दो प्रतिशत पद योग्य चौनमैन को पदोन्नति के आधार पर दिए जा सकेंगे। यह पहली बार है जब चौनमैन को सीधी भर्ती व्यवस्था से बाहर निकालकर लेखपाल पद तक प्रमोशन का अवसर मिलेगा। वर्तमान में लेखपाल के सभी पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में कुल 30837 स्वीकृत पदों में से 21897 पर तैनाती है, जबकि 8940 पद रिक्त हैं। नई व्यवस्था के तहत वे चौनमैन पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जो मौलिक रूप से इसी पद पर नियुक्त हों, भर्ती वर्ष के पहले दिन तक छह वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हों। इन पात्र चौनमैन का चयन चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अनुभवी चौनमैन को लेखपाल के रूप में पदोन्नत करने से न सिर्फ विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी और तेज होगा। इससे आम जनता को राजस्व विभाग की सेवाएं समय पर और अधिक दक्षता के साथ मिल सकेंगी। वित्त मंत्री सुरेशा खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जनपद बागपत में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।



बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन देगी योगी सरकार, 60 साल पूरा होते ही खाते में आने लगेगा धन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फ़ैमिली आईडी 'एक परिवार-एक पहचान' प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह



जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए समाज कल्याण

मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नई व्यवस्था में फ़ैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार होगी, जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। यह सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर

भेजी जाएगी। विभाग सबसे पहले एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप से नहीं मिलेगी, उनसे ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिम्बल के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे और स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा और हर किस्त की जानकारी एसएमएस द्वारा उपलब्ध होगी।

बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर, अपना सीएम बनाने का मौका मिलेगा

बिहार, (एजेंसी)। बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के करीब है, क्योंकि रुझानों में वह 95 सीटों पर आगे है और सहयोगी दलों संग 124 सीटें हासिल कर बहुमत (122) पार कर रही है। यह पार्टी को नीतीश कुमार के बिना सीएम चुनने का मौका देती है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों की माने तो एनडीए 206 सीटों पर आगे चल रहा है। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले भाजपा 95 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अब इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या बिहार में भाजपा का नया मुख्यमंत्री हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा नीतीश के बगैर भी



सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। वर्तमान के आंकड़ों को देखें तो भाजपा 95, लोजपा 20, जीतन राम मांझी और उषेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला लें तो 9 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में यह आंकड़ा 124 का पहुंच रहा है। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू

राजद से गठबंधन करती है। बावजूद इसके वह सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई नहीं देगी। जदयू को 82 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि राजत को सिर्फ 25 सीटें, कांग्रेस तीन और अन्य के खाते में दो सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यह आंकड़ा 111 के आसपास ही पहुंच पा रहा है। अगर असदुद्दीन औवैसी की पार्टी के वि

धायकों को भी इसमें जोड़ा जाए तो यात्रा 116-17 के आसपास जाएगी। ऐसे में बिहार में भाजपा के लिए एक अच्छा मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि भाजपा के तमाम नेता यह बार-बार कह रहे हैं कि यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था और ऐसे में नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं में आंकड़ों को देखने के बाद एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

सरकार जल्द ही दिल्ली को एनसीआर शहरों से जोड़ने वाली बस सेवा शुरू करेगी : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि उनकी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी को विभिन्न एनसीआर शहरों से जोड़ने वाली डीटीसी बस सेवाएं फिर शुरू करेगी। उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा संचालित एक और अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई, जो कश्मीरी गेट टर्मिनल से सोनीपत बस स्टैंड तक चलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें 'एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और जीपीएस सिस्टम' से लैस हैं। गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार को जल्द ही दिल्ली को एनसीआर के आसपास के शहरों से जोड़ने वाली डीटीसी बस सेवाएं फिर शुरू करेगी। उन्होंने सोनीपत के लिए तीन अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली और बड़ौत के बीच पहली अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया था। गुप्ता ने कहा, नयी डीटीसी इलेक्ट्रिक बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये बसें यात्रियों के लिए सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी और दिल्ली-सोनीपत मार्ग पर नियमित रूप से चलेगी, जिससे दोनों शहरों के बीच सुचारु संपर्क सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल गतिशीलता को बढ़ाएगी।



मालेगांव विस्फोट पीड़ितों की याचिका पर एनआईए दाखिल करेगी जवाब

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों, आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) या एनआईए, दोनों में से किसी ने भी पूर्व भाजपा सांसद प्रजा ठाकुर, सेवारत और हाल ही में पदोन्नत कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य को मामले से बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील दायर नहीं की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि वह 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ितों द्वारा दायर अपील पर जवाब दाखिल करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) या एनआईए, दोनों में से किसी ने भी पूर्व भाजपा सांसद प्रजा ठाकुर, सेवारत और हाल ही में पदोन्नत कर्नल प्रसाद पुरोहित और

पांच अन्य को मामले से बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील दायर नहीं की है। जब पीड़ितों द्वारा दायर अपील मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड़ की

अनिल सिंह ने कहा, हम इस पर विचार कर रहे हैं। पीठ ने पाया कि कुछ बरी किए गए लोगों को अभी तक नोटिस नहीं दिए गए हैं और इसलिए वे अदालत में पेश नहीं हुए हैं। पीठ ने

(सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय की ओर से अधिवक्ता प्रकाश सालसिंगकर पेश हुए। सालसिंगकर ने कहा कि वह भी पेशखुश मिलने के बाद जवाब दाखिल करेंगे, जिसमें मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि, सिंह ने इसका पुरजोर खंडन किया और दलील दी कि कागजात व्यवस्थित करने और जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाए। 29 सितंबर, 2008 को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंदे विस्फोटक में विस्फोट हो गया। मामले की जांच करने वाली एटीएस के अनुसार, मोटरसाइकिल प्रजा ठाकुर की थी और आरडीएस सेवारत सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट पुरोहित ने कश्मीर में सैन्य अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हासिल किया था।



पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो अदालत ने एजेंसियों से पूछा कि क्या वे कुछ लिखित दलीलें दाखिल करना चाहती हैं। एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

निर्देश दिया कि पुलिस उन दो आरोपियों को नोटिस तामील कराने में मदद करे जो अपील दायर करने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। ठाकुर और मामले में बरी किए गए मेजर

देश की उपासना

संपादकीय

विस्फोट के बाद बेतुकी बरानबाजी

10 नवंबर को हुए दिल्ली बम धमाके के बाद देश में फिर डर और संदेह का माहौल बन गया है। जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी सब मिलजुल कर रहे, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए जरूरी है कि देश में भीतरी दरारें बनाई जाएं, यह काम दो तरीकों से हो सकता है। पहला डर का माहौल और दूसरा परस्पर भरोसे को तोड़ना। इस समय देश में यही हो रहा है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, जैसे वाक्यों के जरिए बड़ी चालाकी से आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की कोशिशें बरसों से हो रही हैं। दाढ़ी, जालीदार टोपी, बुर्का ये सब संदेह के घेरे में डाल दिए गए हैं। याद पड़ता है कि कोरोना काल में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक ने कोरोना को आतंकवाद की तरह खतरनाक बताते हुए कार्टून प्रकाशित किया था, तो वायरस के मानवीकरण चित्रण में उसे पायजामे, जालीदार टोपी में दिखाया गया था। इसकी खूब निंदा भी हुई थी। लेकिन यह असल में समाज में भीतर तक पैठ चुकी सोच का सबूत है। जब पहलगाम हमला हुआ था, तो आतंकियों ने धर्म पछकर मारा यह बात चर्चा में आई थी। क्योंकि आतंकवादी भी जानते हैं कि इस तरह हम भारत के लोगों में आसानी से फूट डलवा सकते हैं। अभी दिल्ली धमाके से पहले ही फरीदाबाद में जब बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिली तो भाजपा सांसद गिरिराज सिंह का बयान था कि जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने आतंकी पकड़े गए सभी मुसलमान ही क्यों हैं? इस पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा भी है कि गांधी जी को किसने मारा? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? गिरिराज जी के जवाब के बाद हम बात करेंगे। सुशी मुफ्ती का तर्क बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व के अधिकतर देश आतंकवाद का दंश किसी न किसी तरह झेल रहे हैं या झेल चुके हैं और आतंक फैलाने वाले लोग किसी भी मजहब या पंथ के हो सकते हैं। जो लोग आतंकवाद को धर्म से जोड़ते हैं, वे असल में आतंकवाद पर पर्दा डालने का कम करते हैं, जो गंभीर अपराध की तरह देखा जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आतंकवादियों को बचाकर सारा ध्यान बंटया जाता है। गिरिराज सिंह पहले भी राजनैतिक फायदे के लिए बार-बार अपने विरोधियों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देते रहे हैं। हमें नहीं पता कि उनकी अपनी पार्टी के मुस्लिमों को ये बातें कैसी लगती हैं। हो सकता है वे भी राजनैतिक मजबूरी के कारण चुप रहते हों। लेकिन देश का हित राजनैतिक लाभ-हानि से सर्वोपरि है, यह बात उन्हें भी समझनी चाहिए। भाजपा में केवल गिरिराज सिंह ही नहीं हिमंता बिस्वासरमा जैसे नेता भी हैं, जो शिक्षित और अतिवादी होने में फर्क नहीं कर पा रहे। दिल्ली विस्फोट पर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, श्रम में सिखाया गया था कि अगर लोग शिक्षित होंगे, तो कोई अतिवाद नहीं रहेगा। लेकिन आपने देखा कि शिक्षा उन्हें और खतरनाक बनाती है। रॉक्टर बना उनन्हें और भी खतरनाक बनाता है। एक व्यक्ति कभी अपना रंग नहीं बदलता। जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, वे भारतीय नहीं हो सकते। अगर आप भारतीय नहीं हो सकते, तो आप भारत माता को कभी अपनी मां नहीं मान सकते। इसलिए, हमें लगातार सतर्क रहने की जरूरत है।र अपनी राजनैतिक सहूलियत से श्री बिस्वासरमा ने दिल्ली धमाके और वंदे मातरम को आपस में जोड़ दिया, जबकि इसकी कोई तुक नहीं है। दिल्ली आतंकी हमले में डॉ.मोहम्मद उमर को मुख्य आरोपी माना जा रहा है।

चौपियान रहे बिहार के मतदाता

डॉ नीतू कुमारी नवगीत
बिहार की भूमि लोकतंत्र की जन्मदात्री है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से साबित हुआ है कि बिहार के वैशाली में ही लोकतंत्र के प्रथम सफल प्रयोग हुए। बिहार राजनीतिक रूप से एक जागरूक राज्य भी है। लोकतंत्र के भाग्य विधााता मतदाताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार भागीदारी निभाते हुए इस बात की पुष्टि की है कि क्यों देश में बिहार को राजनीतिक रूप से जागरूक और प्रतिनिधि राज्य माना जाता है। चुनाव आयोग द्वारा जो अनंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार इस बार के चुनाव में 66.91 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के 73 सालों के चुनावी इतिहास में पहली बार राज्य के मतदाताओं ने इतनी बम्पर वोटिंग की है।इससे पहले वर्ष 2000 में 62.57 प्रतिशत मतदान हुआ था । बिहार की महिलाएं लगातार बढ़त बनाई हुई हैं । इस बार भी महिलाओं ने पुरुषों से लगभग 8.8 प्रतिशत अधिक मतदान किया है । भारत निर्वाचन आयोग ने इसको विशेष मतदाता पुनरीक्षण और व्यापक जन भागीदारी सहित सभी सम्बंधित पदाधिकारी और जनजागरूकता से जुड़े लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया है । भारतीय संविधान लागू होने के उपरांत मतदाताओं की भागीदारी के आधार पर यह बिहार का सबसे सफल चुनाव रहा। महिला मतदाताओं का जोश पुरुष मतदाताओं से भी अधिक रहा। दूसरे चरण के मतदान में 74ल् से भी अधिाक महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों चरणों के मतदान के दौरान महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। कुल मिलाकर जहां 65.08 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया वहीं 68.76 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई। बिहार की महिलाओं की यह सजगता काबिले तारीफ है। चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान की स्वीप आइकॉन के रूप में जहां कहीं भी मैं मतदाताओं की मतदान की जरूरत के संसंध में बताते नई, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। बिहार के लोग चुनाव को लेकर उत्साहित रहते हैं। इस बार मतदाताओं ने चुनाव को उत्सव के रूप में मनाया। लोक आस्था के महान पर्व छठ के ठीक बाद हुए चुनाव में मतदाताओं ने वैसे ही बढ़-कर कर भाग लिया जैसे अपने लोकोत्सव को मनाया। मतदान प्रक्रिया में इतनी अच्छी भागीदारी लोकतंत्र की जीत है, बिहार की जीत है। चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने में 8.5 लाख से अधिक कर्मचारियों, 1.4 लाख से अधिक पोलिंग एजेंट, 243 जनरल ऑब्जर्वर, 38 पुलिस ऑब्जर्वर, 67 एकस्पेंडिचर ऑब्जर्वर ने भी अपनी भूमिका निभाई। सभी अपनी शानदार भूमिका के लिए बधाई के पात्र हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया को देखने और समझने के लिए दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपींस, बेल्जियम और कोलंबिया के 16 प्रतिनिधि भी आए जिन्होंने बिहार में हुए इस शानदार चुनाव और जनता के उत्साह को देखा, समझा और महसूस किया।वस्तुतः लोकतंत्र का महापर्व चुनाव ही है। पिछले कुछ चुनाव में जनता की कम भागीदारी चिंता का विषय रहा है लेकिन इस बार बिहार के मतदाताओं ने नई राह दिखाई है। अपार उत्साह और रिर्कोर्ड वोटिंग के साथ उन्होंने संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था है। आगे का काम जनप्रतिनिधियों का होगा। चुनावी प्रक्रिया में जिन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा, उन सब को जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना होगा। अपनी भूमिका सशक्त तरीके से निभानी होगी ताकि जनता का भरोसा न सिर्फ उन पर बना रहे, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी बना रहे। जय लोकतंत्र जय बिहार की जनता ।(डॉ नीतू कुमारी नवगीत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पटना जिला में निर्वाचन आयोग की मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप आइकॉन रही। वह बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं।)

विचार

महागठबंधन आगे, पर नतीजा अभी दूर है

राजेंद्र वास्तव में, मतदाता सूचियों की इस पहलू से छानबीन करने वाले कुछ अध्ययनों में यह सचाई सामने आयी है कि कुछ आठ करोड़ मतदाताओं में संघ–भाजपा की परिभाषा के हिसाब से घुसपैठिया या मुसलमान विदेशी कहे जा सकने वालों की संख्या,



आधा दर्जन भी नहीं निकलेगी। विदेशियों की गिनाते लाइक गंधी हैं और नेपालियों की ही पायी गयी है और उसमें भी बड़ा हिस्सा विवाह कर बिहार के नेपाल से लगती सीमाओं वाले जिलों में रह रही नेपाली बहुओं का है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, बिहार में चुनाव प्रचार के ही अंतिम चरण तक आते–आते, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने, अपना

नवफालों से सावधान, क्योंकि

सर्वमित्रा
भारतीय पत्रकारिता के पुरखों ने जिन कष्टों के साथ जनता की आवाज को उठाने का काम किया है, उसी अपने फसल आज के पत्रकार का रहत है हैं। आजादी के वक्त अंग्रेजी कि शासन की नाराजगी के खतरे मोल लेकर, कम साधनों के साथ पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित होते थे, ताकि जनता में आजादी और बाकी की एक प्रतियत फर्जी खबरश बताया था। इसके दो दिन बाद ही बीबीसी में दो बड़े इस्तीफे हो गए। गौरतलब है कि बीबीसी पर हाल के वर्षों में निष्पक्ष समाचारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने में विफल रहने के, साथ ही ध्रुवीकृत हो चुके राजनीतिक और सामाजिक माहौल के एक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को गलत संदर्भ में दिखाने के आरोप लगे थे। व्हाट हाउस ने बीबीसी को श्रोपेंगेंडा मशीनर (प्रचार मशीन) करार दिया था। बीबीसी के पैनोरमा कार्यक्रम में ट्रंप के तथ्य का दो हिस्सों को एक साथ इस तरह संपादित किया गया था, मानो ट्रंप जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। ज्ञात हो कि ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति चुनाव हार गए और और तब उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था, जो अमेरिका के लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती माना गया था। इस प्रकरण पर बीबीसी की पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप अपने समर्थकों

ऋण के जाल में फसे

प्रह्लाद
वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अ विकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टरूप दिख रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त घुटा उनकी की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारणों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों

कुछ भी नहीं था। वास्तव में झारखंड के विधानसभाई चुनाव में मोदी ने, जिस तरह पूरे गले से यह राग गाया था, उसके बाद उनके लिए अपने इस राग में जोड़ने के लिए कुछ खास नया रहता ही नहीं था। हां! झारखंड से भिन्न बिहार में बहन–बेटियों के लिए खतरे का, उनके बहन–बेटियों को ले जाने का डर नहीं दिखाया जा रहा था। उल्टे भाजपा की शीर्ष जोड़ी ने और उसमें भी खासतौर पर अमित शाह ने अपने श्रोताओं में जोश पैदा करने की उचमीद में, बिहार में यह नया आश्वासन जरूर जोड़ा कि घुसपैठियों ने जो धंधे खड़े कर लिए हैं और जमीनें हासिल कर ली हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। बेशक, घुसपैठियों के मुद्दे को झारखंड की तरह, प्रधानमंत्री और उनके नंबर–दो के पहले दिन से ही बिहार में अपने चुनाव प्रचार की मुख्य थीम नहीं बनाने की वजह, कम से कम इस खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक दुहाई का उस्तेमाल करने में उनकी किसी हिकच में नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह, बिहार में भाजपा की सत्ता तक पहुंचने के लिए गठजोड़ी की और वह भी एक ऐसे नेता, नीतीश कुमार को आगे रखकर गठजोड़ बनाए रखने की मजबूरी थी, जिनकी पार्टी जदयू को गठजोड़ का खुले तौर पर सांप्रदायिक

रुख अपनाया मंजूर नहीं था। इसके ऊपर से बिहार के ही संदर्भ में, घुसपैठियों के मुद्दे को भुनाने में एक

कठिनाई और थी। बिहार में विधानसभाई चुनाव से ऐन पहले, विपक्ष की सारी आपत्तियों को अनसुना करते हुए चुनाव आयोग द्वारा अचानक मतदाता सूचियों के लिए खतरे का, उनके बहन–बेटियों को ले जाने का डर नहीं दिखाया जा गया था, उसके जरूरी होने के कारण के रूप में, सूचियों में बड़ी संक्चया में गैर– नागरिकों की मौजूदगी का दावा किया गया था। इसे संघ–भाजपा द्वारा न सिर्फ एसआइआर कराने के उच्चत फैसेले के बचाव के लिए बल्कि आम हैं और जमीनें हासिल कर ली हैं, हिस्से के तौर पर, खूब उछाला भी गया था। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान में अपनी आवाज जोड़ी थी और विपक्ष को घुसपैठियों का संशंक बताया था। लेकिन, इस सब के बावजूद, एसआइआर की प्रक्रिया जब पूरी हुई और चुनाव आयोग द्वारा अपनी ओर से अंतिम और जाहिर हैं कि श्शुद्घ की हुईश्श मतदाता सूचियां जारी की गयीं, उसमें हटाए गए नामों के लिए गठजोड़ी की और वह भी एक ऐसे नेता, नीतीश कुमार को आगे रखकर गठजोड़ बनाए रखने की मजबूरी थी, जिनकी पार्टी जदयू को गठजोड़ का खुले तौर पर सांप्रदायिक

देशों से भारत के राज्यों को मिलती है सीख

गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्धथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं– जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221. 5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)। ग्रीस, घाना, हैती, मोंगोबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डवांवडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया

जौनपुर, शुक्रवार, 14 नवम्बर 2025 2

अभी दूर है

अध्ययनों में यह सचाई सामने आयी है कि कुछ आठ करोड़ मतदाताओं में, संघ–भाजपा की परिभाषा के हिसाब से घुसपैठिया या मुसलमान विदेशी कहे जा सकने वालों की संख्या, आधे दर्जन भी नहीं निकलेगी। विदेशियों की गिनाते लाइक संख्या, नेपालियों की ही पायी गयी है और उसमें भी बड़ा हिस्सा विवाह कर बिहार के नेपाल से लगती सीमाओं वाले जिलों में रह रही नेपाली बहुओं का है। क्योंकि घुसपैठियों के खतरे के झूठ की पोल खोलने वाले एसआइआर के ये आंकड़े एकदम हाल के हैं, फैसेले के बचाव के लिए बल्कि आम तौर पर अपने सांप्रदायिक प्रचार के उछालने से अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के सिवा किसी भी खास लाभ की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए, प्रधानमंत्री समेत संघ–भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने चुनाव प्रचार में घुसपैठियों के मुद्दे से आना तौर पर परे छोड़ दिया। लेकिन, ऐसा लगता है कि पहले चरण में 121 की सीटों के मतदान में जिस तरह के रुझान दिखाई दिए, उनके बाद संघ–भाजपा को हताशा के उपाय के तौर पर घुसपैठियों का खतवा प्रचारित यह बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। वास्तव में, मतदाता सूचियों की इस पहलू से छानबीन करने वाले कुछ

क्योंकि खेद नहीं है

यानी टीवी पर निजी चैनलों की बाढ़ आने के बाद से तो जनता तक सही सूचनाएं पहुंचाने की जवाबदेही से तो जनता को ही इस पर सोचना पत्रकारों ने बिल्कुल ही हाथ झटक दिया। अब जनता को टार्गेट (लक्ष्य) की तरह देखा जाता है कि इसे कैसे अपने चंगुल में फसाया जाए। शुरुआत



नाग–नागिन, भूतिया महल, चमत्कारी बाबा जैसे समाचारों से हुई, जनता को समाचारों के बीच इस तरह का मनोरंजन तकलीफ और निमोनिया होने के पूरी तरह किनारे कर केवल मनोरंजन आगे कर दिया गया और अब नफरत ही सबका का प्रधानतत्व हो गई है। टीवी की बहसों के बीच मार–पीट, अपशब्दों का प्रयोग होने लगे तो जनता को समझ लेना चाहिए कि उसे किस कदर गिरा हुआ मानकर उसे खबरें परोसी जा रही हैं। यह

परेशान दिखीं। दरअसल उनके पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र को लगभग तीन हफ्ते पहले सांस लेने में

पेशान दिखीं। दरअसल उनके पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र को लगभग तीन हफ्ते पहले सांस लेने में पसंद आ गया तो फिर समाचारों को पूरी तरह किनारे कर केवल मनोरंजन आगे कर दिया गया और अब नफरत ही समाचारों का प्रधानतत्व हो गई है। टीवी की बहसों के बीच मार–पीट, अपशब्दों का प्रयोग होने लगे तो जनता को समझ लेना चाहिए कि उसे खबरें परोसी जा रही हैं। यह



